

न्यूज़ टुडे

FATF ने 'कम्प्रेहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क्स' रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट दर्शाती है कि आतंकवादी संगठन अब भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करके अपने कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं और हमलों की योजना बना रहे हैं।

➤ आतंकवाद के वित्त-पोषण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक:

- ⊕ अकेले सक्रिय आतंकवादी और न्यूनतम वित्त-पोषण की आवश्यकता वाले छोटे संगठन;
- ⊕ अफ्रीका और दक्षिण एशिया में असुरक्षित एवं छिद्रिल सीमाएं;
- ⊕ आतंकवाद को कुछ देशों द्वारा दिया जा रहा राज्य-स्तरीय समर्थन;
- ⊕ मुक्त व्यापार क्षेत्र की कमजोर निगरानी व नियमों की कमी आदि।

आतंकवाद के वित्त-पोषण के माध्यम

➤ पारंपरिक तरीके: अल-शबाब और हमास जैसे समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नकद आधारित लेन-देन, हवाला एवं अन्य अनौपचारिक तरीके, जिनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

➤ नई पद्धतियां:

- ⊕ डिजिटल प्लेटफॉर्म:
 - ◆ सोशल मीडिया, क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन मार्केटप्लेस के जरिए धन एकत्रित करना;
 - ◆ बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी का उपयोग करना;
 - ◆ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंड ट्रांसफर करना आदि।
- ⊕ आपराधिक गतिविधियां: जबरन वसूली, फिरौती के लिए अपहरण, मादक पदार्थों की तस्करी, और बोको हरम जैसे समूहों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों (जैसे- सोना, लकड़ी आदि) का अवैध व्यापार।
- ⊕ गैर-लाभकारी और कानूनी संस्थाओं का दुरुपयोग:
 - ◆ फ्रंट कंपनियों और शेल कंपनियों के जरिए धन छिपाना;
 - ◆ गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) से फंड को डाइवर्ट कर आतंकी गतिविधियों में लगाना आदि।



आतंकवाद के वित्त-पोषण (Counter-Terrorism Financing – CTF) को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें:

- जोखिम संकेतकों की पहचान करना: जैसे- बार-बार उच्च जोखिम वाले देशों को धन अंतरण, वर्चुअल असेट्स (VAs) और प्रीपेड कार्ड जैसे गुमनामी बढ़ाने वाले उपकरणों का उपयोग आदि की निगरानी करनी चाहिए।
- संगठित बहुपक्षीय प्रतिक्रिया: आतंकवाद के वित्त-पोषण की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) प्रतिबंधों के तहत आतंकवादी संगठनों को बहुपक्षीय रूप से सूचीबद्ध करना चाहिए।
- FATF मानकों से बाहर के क्षेत्रों तक पहुंच: सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म से उत्पन्न खतरों को बेहतर ढंग से समझने तथा उनसे निपटने के लिए लक्षित सार्वजनिक-निजी साझेदारी (PPPs) विकसित करनी चाहिए।

केंद्र सरकार ने आकांक्षी DMF कार्यक्रम लॉन्च किया

केंद्रीय खान मंत्रालय ने 'आकांक्षी DMF कार्यक्रम' के लिए परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) के साथ जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) पहलों को जोड़ना है।

- ये दिशा-निर्देश प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) पर आधारित हैं। इस योजना का उद्देश्य जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधि के माध्यम से खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों का विकास करना है।
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP) नीति आयोग की पहलें हैं। इनका उद्देश्य देश भर में सबसे अविकसित जिलों/ब्लॉक्स को तेजी से और प्रभावी ढंग से बेहतर बनाना है।

आकांक्षी DMF कार्यक्रम के बारे में

➤ उद्देश्य: DMF कार्यों को ADP/ ABP के प्रमुख क्षेत्रों और प्रदर्शन संकेतकों के साथ जोड़ना, ताकि खनन से प्रभावित समुदायों के लिए बेहतर लाभ व अच्छे परिणाम मिल सकें।

➤ इसके तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रक:

- ⊕ स्वास्थ्य और पोषण;
- ⊕ शिक्षा;
- ⊕ कृषि एवं जल संसाधन;
- ⊕ कृषि व संबद्ध गतिविधियां;
- ⊕ अवसंरचना;
- ⊕ सामाजिक विकास;
- ⊕ वित्तीय विकास और कौशल विकास।

➤ आकांक्षी जिलों और ब्लॉक्स की पहचान करना: वर्तमान में, 106 आकांक्षी जिलों और 473 आकांक्षी ब्लॉक्स को DMF के साथ जोड़ा गया है तथा इनकी संख्या में समय के साथ बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) के बारे में

➤ DMF की स्थापना खान और खनिज (विकास और विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957 की धारा 9(B) के तहत की गई है। यह धारा 2015 में संशोधन के माध्यम से अधिनियम में जोड़ी गई थी। DMF एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में काम करता है।

➤ उद्देश्य: खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य करना।



पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम, 2025 का मसौदा जारी किया

ये नियम पुराने पेट्रोलियम रियायत नियम, 1949 तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 का स्थान लेंगे। साथ ही, ये नियम ऑयल फील्ड्स (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के हालिया संशोधन के भी अनुरूप हैं।

मुख्य मसौदा नियमों पर एक नजर:

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए विस्तृत आवश्यकताओं को पूरा करने की शुरुआत; कार्बन कैप्चर और भंडारण (CCS) के लिए एक विनियामक फ्रेमवर्क स्थापित करना; और न्यूनतम पांच वर्षों के लिए पोस्ट-क्लोजर निगरानी के साथ साइट बहाली कोष को अनिवार्य बनाना।
- एकीकृत नवीकरणीय और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली परियोजनाएं शुरू करना: ये नियम ऑपरेटर्स को तेल क्षेत्र ब्लॉक्स के भीतर सौर, पवन, हाइड्रोजन और भूतापीय ऊर्जा परियोजनाएं शुरू करने की अनुमति देते हैं।
- स्थिरीकरण खंड: इसे निवेशकों को भविष्य के कानूनी या वित्तीय परिवर्तनों (जैसे- करों में वृद्धि) के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें मुआवजे या कटौती की अनुमति दी गई है।
- घोषणा: अवसंरचना के दोहराव को कम करने और लघु फर्मों को प्रोत्साहित करने के लिए पाइपलाइनों एवं अन्य सुविधाओं में कम उपयोग की गई क्षमता की घोषणा करना अनिवार्य है।
- एक समर्पित निर्णायक प्राधिकरण का निर्माण: यह अनुपालन संबंधी प्रावधानों को लागू करने, विवादों को हल करने और दंड लगाने के लिए अधिकृत होगा।
- डेटा गवर्नेंस: अन्वेषण और उत्पादन के दौरान उत्पन्न सभी परिचालन आंकड़े और भौतिक नमूने केंद्र सरकार के स्वामित्व में होंगे। पट्टेदार इस डेटा का आंतरिक रूप से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्यात या बाहरी उपयोग के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है।

सुधारों के उद्देश्य



इन-स्पेस (In-SPACe) ने स्टारलिंग को भारत में सैटेलाइट सेवाएं प्रदान करने के लिए 5 साल हेतु लाइसेंस प्रदान किया

स्पेसएक्स की स्टारलिंग पृथ्वी की निचली कक्षा (Low Earth Orbit) में स्थापित एक उपग्रह समूह प्रणाली है। इसका उद्देश्य वैश्विक इंटरनेट कवरेज प्रदान करना है। स्टारलिंग स्पेसएक्स की एक कंपनी है।

■ In-SPACe द्वारा प्रदान की गई मंजूरी, भारत के उपग्रह संचार क्षेत्र को अधिक खुला बनाने और अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी भागीदारी बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

उपग्रह संचार सेवाओं (Satellite Communication Services) के बारे में

- परिभाषा: यह एक वायरलेस इंटरनेट सेवा है, जो संचार उपग्रहों (Communication Satellites) के जरिए प्रदान की जाती है। साथ ही, यह जमीन पर मौजूद नेटवर्क (जैसे केबल या टावर) पर निर्भर नहीं होती।
- मुख्य उपयोगकर्ता: टीवी प्रसारक (Broadcasters), इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISPs), सरकारें, सेना और बड़ी कंपनियां।
- प्रकार: टेलीकॉम सेवाएं, प्रसारण सेवाएं, डेटा कम्युनिकेशन सेवाएं आदि।
- महत्व: पूरी दुनिया में फास्ट कनेक्टिविटी (दूरदराज के इलाकों में भी इंटरनेट सुविधा) मिलेगी; आपातकाल और आपदा राहत कार्यों में मदद मिलेगी तथा नेविगेशन एवं दिशा-निर्देश में सहायक होंगी।

अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ाने से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलें

- एंट्रिक्स (Antrix): यह इसरो (ISRO) की व्यावसायिक शाखा के रूप में कार्य करता है।
- अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार (2020): इसके जरिए इसरो, IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) तथा NSIL (न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड) के बीच स्पष्ट भूमिका का विभाजन किया गया है। साथ ही, निजी कंपनियों की व्यापक भागीदारी को संभव बनाया गया है।
- भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023: यह गैर-सरकारी संस्थाओं (Non-Government Entities - NGEs) को समान अवसर प्रदान करती है, जिससे वे अंतरिक्ष से जुड़ी पूरी मूल्य श्रृंखला में भाग ले सकें।
- इसरो कई स्टार्ट-अप्स (जैसे कि अग्रिकुल कॉसमॉस) को समर्थन दे रहा है, ताकि वे अपने निजी भारतीय लॉन्च व्हीकल्स विकसित कर सकें। इसमें इसरो द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति भी शामिल है।
- भारत का पहला सब-ऑर्बिटल लॉन्च एक निजी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा नवंबर 2022 में किया गया था। इसे IN-SPACe ने संभव बनाया था। स्काईरूट एयरोस्पेस के लॉन्चिंग रॉकेट का नाम विक्रम-एस था।



IN-SPACe (भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र) के बारे में

- यह अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है।
- इसकी स्थापना 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों के हिस्से के रूप में की गई थी, ताकि निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जा सके।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक और निजी सहयोग के माध्यम से भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।
- साथ ही, यह अगले पांच वर्षों में अंतरिक्ष क्षेत्र संबंधी स्टार्ट-अप्स के लिए एक विशेष वेंचर कैपिटल फंड का प्रबंधन भी करेगा, ताकि नवाचार को बढ़ावा मिले और एक जीवंत (सक्रिय) स्पेस इकोसिस्टम तैयार किया जा सके।

नामीबिया UPI आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश बनेगा

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने नामीबिया की यात्रा की थी। इस दौरान, नामीबिया ने रियल टाइम में डिजिटल भुगतान के लिए UPI प्रणाली को अपनाने हेतु एक लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया था।

इससे पहले, RBI ने 2023-24 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) के साथ मिलकर 2028-29 तक 20 देशों में UPI को पहुंचाने पर काम करने का एजेंडा निर्धारित किया था।

निम्नलिखित देश UPI-आधारित अंतर्राष्ट्रीय मचेंट भुगतान स्वीकार करते हैं-

⊕ भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात।

UPI के बारे में

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने लॉन्च किया था। यह एक त्वरित भुगतान प्रणाली है। यह कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में जोड़ता है। इसमें कई बैंकिंग सुविधाओं सहित सुगम फंड ट्रांसफर और मचेंट पेमेंट आदि शामिल हैं।

UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण का महत्व

वैश्विक बाजार में विस्तार: तीव्र एवं आसान सीमा-पार भुगतान भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दे सकता है।

इंटरऑपरेबिलिटी और मानकीकरण: UPI को व्यापक रूप से अपनाने से विभिन्न देशों में भुगतान प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। इससे विश्व भर में वित्तीय प्रौद्योगिकियों के साथ सहज एकीकरण सुनिश्चित होगा।

‘डिजिटल’ कूटनीति: तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारत के प्रभाव और ख्याति को मजबूती मिलेगी।

UPI के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए उठाए गए अन्य कदम

NIPL: यह भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसे भारत के बाहर रुपये और UPI के प्रसार को बढ़ाने के लिए 2020 में स्थापित किया गया था।

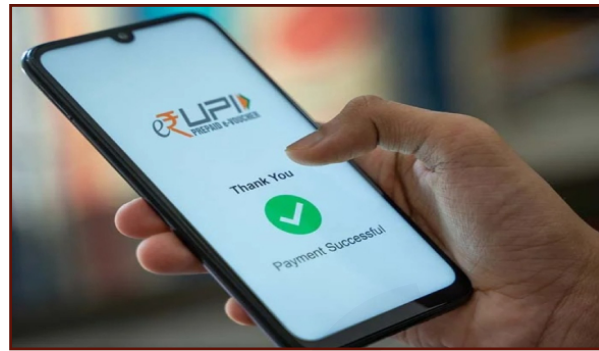
UPI वन वर्ल्ड: G-20 देशों से आने वाले विदेशी नागरिकों/ NRIs को UPI से जुड़ा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट प्रदान किया जाता है।

G-20 के अंतर्गत भारत की पहलें:

⊕ ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) रिपोजिटरी;

⊕ ग्लोबल साउथ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक प्रभाव निधि आदि।

नोट: UPI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की पेमेंट लेयर का एक अभिन्न अंग है।



अन्य सुर्खियां



INS निस्तार

हाल ही में, स्वदेशी रूप से डिजाइन और विनिर्मित भारत का पहला डाइविंग सपोर्ट पोत ‘आईएनएस निस्तार’ भारतीय नौसेना को सौंपा गया।

INS निस्तार के बारे में

यह अत्याधुनिक डाइविंग उपकरणों से लैस है। यह 300 मीटर की गहराई तक डीप-सी सैचुरेशन डाइविंग करने में सक्षम है।

इसमें समुद्र में 75 मीटर गहराई तक डाइविंग ऑपरेशन करने के लिए एक साइड डाइविंग स्टेज भी है।

यह पोत डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल (DSRV) के लिए ‘मदर शिप’ के रूप में कार्य करेगा, जो समुद्र में कर्मियों को बचाने और निकालने के कार्य में सहायक होगा।

यह कई रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (ROVs) के संयोजन में कार्य करता है, जो 1000 मीटर की गहराई तक डाइवर मॉनिटरिंग और बचाव कार्यों को अंजाम दे सकते हैं।



एक्सटेंडेड रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ERASR)

भारत ने स्वदेशी एंटी-सबमरीन रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया है।

एक्सटेंडेड रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ERASR) के बारे में

यह एक पूर्णतया स्वदेशी पनडुब्बी-रोधी रॉकेट है। इसका उपयोग शत्रुओं की पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसे भारतीय नौसेना के जहाजों से दागा जाता है।

इसमें दिन-रॉकेट मोटर कॉन्फिगरेशन होता है, जो उच्च सटीकता और निरंतरता के साथ अलग-अलग दूरी पर स्थित लक्ष्यों को निशाना बना सकता है।

इसमें स्वदेशी रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज का उपयोग किया गया है।

इसका डिजाइन और विकास DRDO की पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE) द्वारा किया गया है।



शैडो बैंकिंग

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) अब शैडो बैंक नहीं रह गई हैं। शैडो बैंकिंग के बारे में

शैडो बैंकिंग का मतलब है वित्तीय मध्यवर्तियों और संस्थाओं का एक नेटवर्क जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे से बाहर कार्य करते हैं। इन्हें पारंपरिक बैंकों की तरह सख्त विनियामकीय कानूनों का पालन नहीं करना होता है।

मुख्य चिंताएं: ऐसी संस्थाओं के संचालन में पारदर्शिता की कमी होती है। साथ ही, संचालन के क्रम में इन पर कई प्रकार के वित्तीय संकटों का सामना करने का खतरा बना रहता है।

भूमिका: ये संस्थाएं अलग-अलग क्षेत्रों को ऋण और लिक्विडिटी प्रदान करके वैश्विक वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उदाहरण: मनी मार्केट फंड्स, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, सिक्यूरिटाइजेशन और एसेट-बैकड सिक्योरिटीज़।



कैटस्ट्रोफी बॉण्ड (कैट बॉण्ड)

कैट बॉण्ड (Catastrophe Bonds) अपेक्षाकृत नए प्रकार का वित्तीय साधन है। यह प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की योजना बनाने में मदद कर सकता है।

कैट बॉण्ड्स के बारे में

यह एक वित्तीय साधन (Financial instrument) है, जो विनाशकारी आपदा को कवर करने वाले बीमा जोखिम को निवेशकों के बीच वितरित कर देता है। ऐसे बॉण्ड्स के निवेशकों को उच्च लाभ प्राप्त होता है, लेकिन यदि कोई सूचीबद्ध आपदा घटित होती है तो मूलधन का नुकसान भी हो सकता है।

इनमें भूकंप, हरिकेन, बाढ़ और अन्य चरम आपदाएं शामिल हो सकती हैं।

इसमें निवेशकों को उच्च यील्ड (ब्याज) प्राप्त हो सकता है। हालांकि, यदि बॉण्ड की परिपक्वता से पहले कोई सूचीबद्ध प्राकृतिक आपदा घटित हो जाती है, तो उन्हें मूलधन का नुकसान भी हो सकता है।

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती घटनाएं बीमा उद्योग में कैट बॉण्ड्स को और अधिक लोकप्रिय बना रही हैं।



एडमिरल्टी (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017

केरल सरकार ने जहाज डूबने की वजह से पर्यावरण को हुए नुकसान के लिए एडमिरल्टी अधिनियम 2017 (Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act) के तहत मुआवजे की मांग की है।

अधिनियम के बारे में

- लागू होना: यह अधिनियम हर प्रकार के पोत (जहाज) पर लागू होता है, चाहे उसके मालिक का निवास स्थान या डोमिसाइल किसी भी देश में हो।
- कवर किए गए सामुद्रिक क्लेम के प्रकार: जहाजों को हुई क्षति, स्वामित्व और समझौते संबंधी विवाद, समुद्री जीव-जंतुओं की हानि, समुद्री क्षेत्र के कर्मियों के पारिश्रमिक संबंधी मुद्दे, पर्यावरण को नुकसान।
- न्यायिक-अधिकार क्षेत्र: संबंधित उच्च न्यायालयों में निहित होना चाहिए।
- क्षति के लिए मुआवजा: यह अधिनियम, हुए नुकसान, सुधारात्मक कदम और पूर्व-स्थिति बहाली पर हुए खर्च के लिए मुआवजे की व्यवस्था करता है।
- क्लेम का निपटारा होने या सिक्योरिटी राशि जमा किए जाने तक जहाज को रोककर रखा जा सकता है।



तुर्काना झील

वैज्ञानिकों ने तुर्काना झील में खोजी गई विलुप्त स्तनधारियों के दांतों की एनामेल से 18 से 20 मिलियन वर्ष पुराने प्रोटीन निकालने में सफलता प्राप्त की है।

तुर्काना झील के बारे में

- इस झील का मूल नाम रुडोल्फ झील था। इसे जेड सागर भी कहा जाता है।
- अवस्थिति: इस झील का अधिकांश हिस्सा उत्तरी केन्या में है। इसका कुछ हिस्सा इथियोपिया में भी है।
- सतह क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है। साथ ही, यह दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी रेगिस्तानी-झील है।
- लेक तुर्काना नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। तुर्काना झील इस पार्क का हिस्सा है।
- झील में मिलने वाली एकमात्र बारहमासी सहायक नदी: ओमो नदी।



एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम

हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रूप से निर्मित 'एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स (ATAGS)' परियोजना को "अनुकरणीय मिशन मोड सफलता" करार दिया।

ATAGS के बारे में

- डिज़ाइनर: यह सिस्टम DRDO की पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE) प्रयोगशाला द्वारा डिज़ाइन की गई है।
- यह एक बड़ी तोप (गन) है। यह लंबी दूरी तक सटीक हमला करने के लिए गाइडेड मिसाइलें दाग सकती है।
- इसमें एक इलेक्ट्रिक प्रणाली है, जिसे कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। इस तरह यह लंबे समय तक विश्वसनीय रूप से कार्य करती है।
- इसमें एक ऑटोमेटिक एम्बुशन हैंडलिंग सिस्टम है, जिसमें क्रेन भी शामिल है।



माही या महिसागर नदी

हाल ही में, गुजरात में माही नदी पर बना एक पुल ढह गया।

माही नदी के बारे में

- नदी का प्रकार: यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली बड़ी अंतरराज्यीय नदी है। इसकी विशालता के कारण इसे 'महिसागर' भी कहा जाता है।
- उद्गम स्थल: यह नदी मध्य प्रदेश में धार जिले के सरदारपुर के पास विंध्याचल की उत्तरी ढलान से निकलती है।
- संगम: यह नदी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है।
- अंतराज्यीय नदी: यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है।
- स्थलाकृतिक सीमाएँ
 - उत्तर और उत्तर-पश्चिम: अरावली पहाड़ियाँ,
 - पूर्व: एक कटक (रिज), जो इसे चंबल बेसिन से अलग करता है।
 - दक्षिण: विंध्य पर्वतमाला,
 - पश्चिम: खंभात की खाड़ी।
- अन्य विशेषताएं:
 - यह भारत की उन कुछ नदियों में शामिल हैं जो कर्क रेखा को दो बार काटती हैं।
 - यह नदी टेढ़ी-मेढ़ी धारा या विसर्प बनाती है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली अन्य नदियों में ऐसी विशेषता कम दिखती है।

सुर्खियों में रहे स्थल



सिएरा लियोन (राजधानी: फ्रीटाउन)

दक्षिणी सिएरा लियोन के टर्टल आइलैंड्स में स्थित न्यांग्गाई बढ़ते समुद्री-जलस्तर के कारण अपना दो-तिहाई हिस्सा खो चुका है।

भौगोलिक अवस्थिति

- अवस्थिति: पश्चिमी अफ्रीकी देश
- स्थलीय सीमाएँ: उत्तर और पूर्व में गिनी और दक्षिण में लाइबेरिया से लगती हैं।
- समुद्री सीमाएं: पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है।

भौगोलिक विशेषताएं:

- प्राकृतिक संसाधन: हीरे, क्रोमाइट, सोना, बॉक्साइट, और रूटाइल (टाइटैनियम डाइऑक्साइड) के भंडार।
- जलवायु: यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय (tropical) है। बारी-बारी से वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु का चक्र चलता रहता है।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर